अवैध उत्खनन वैध ठेका नहीं होने से बेखौफ अवैध कारोबारी, पुलिस, वन और राजस्व अमले ने साधी चुप्पी

बारिश थमने पर रेत माफिया सक्रिय

नवभारत, शहडोल । बारिश का दौर थमते ही जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का खेल फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। जिले के अलग-अलग इलाकों में नदी-नालों से रेत निकालकर ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा के जरिए परिवहन किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। जैतपुर, केशवाही, सोहागपुर, गोहपारू, जयसिंहनगर और ब्यौहारी क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालात यह हैं कि प्राकृतिक जलस्रोतों की निगरानी के लिए जिम्मेदार तंत्र की मौजूदगी के बावजूद रेत का कारोबार बेरोकटोक चलने के आरोप लग रहे हैं।



नदियों में मशीनों की दस्तक

जिले में पिछले वर्ष से रेत का वैध ठेका नहीं होने की स्थिति ने अवैध कारोबारियों के लिए रास्ता आसान कर दिया है। वैध व्यवस्था के अभाव में नदी-नालों से रेत निकालने और उसे निर्माण कार्यों में खपाने का अवैध सिलसिला बढ़ने की बात सामने आ रही है। इससे एक ओर शासन को करोड़ों रुपये के संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का बेतरतीब दोहन भी जारी है।जानकारों का कहना है कि जब रेत की वैध आपूर्ति व्यवस्था कमजोर होती है तो निर्माण कार्यों की मांग को पूरा करने के लिए अवैध उत्खनन को बढ़ावा मिलता है। यही वजह है कि बारिश खत्म होते ही रेत परिवहन में लगे वाहनों की आवाजाही बढ़ने लगती है।

बिगड़ रहा प्राकृतिक संतुलन

अवैध रेत उत्खनन का सबसे गंभीर असर नदियों और छोटे-बड़े नालों पर पड़ता है। जरूरत से ज्यादा रेत निकालने से नदी का प्राकृतिक स्वरूप बदलने, जलधारा प्रभावित होने और तटों के कटाव का खतरा बढ़ जाता है। कई स्थानों पर रेत की परत हटने से नदी तल असामान्य रूप से गहरा होने की स्थिति बनती है, जिसका असर आसपास के भूजल स्तर और पर्यावरणीय संतुलन पर भी पड़ सकता है। बरसात के दौरान जिन नदी-नालों में पानी का तेज बहाव रहता है, उन्हीं जलस्रोतों में बारिश थमते ही रेत निकालने का दबाव बढ़ जाता है। यदि समय रहते इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में प्राकृतिक जलस्रोतों के अस्तित्व और उनके प्रवाह तंत्र पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है।

इनका कहना है

जिले के लिए रेत के टेण्डर प्रक्रिया की कार्यवाही प्रचलन में हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सुरक्षित है, लगभग 1 सप्ताह के भीतर आदेश आने की संभावना है, आदेश आते ही टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और जिले में वैध रेत ठेका प्रारंभ हो सकेगा।

राहुल शांडिल्य, जिला खनिज अधिकारीजिला शहडोल

सरकारी खजाने को चूना, निगरानी तंत्र नींद में

रेत के अवैध उत्खनन से सिर्फपर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि शासन को मिलने वाला खनिज राजस्व भी प्रभावित होता है। वैध ठेका नहीं होने के कारण शासन को राजस्व प्राप्ति का बड़ा अवसर हाथ से निकल रहा है और दूसरी तरफअवैध कारोबारी प्राकृतिक संसाधन को बिना वैध रॉयल्टी के बाजार तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि नदी-नालों से लगातार रेत निकाली जा रही है और भारी वाहनों से उसका परिवहन हो रहा है, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था कहां है। पुलिस, वन, राजस्व और खनिज विभाग के बीच समन्वित निगरानी की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। कार्रवाई के नाम पर कभी-कभार वाहन पकड़ लेने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।

प्राचार्य से तंग आए 200 छात्र पैदल कलेक्ट्रेट रवाना

प्रशासन को खबर लगते ही भेजी बस,एकलव्य विद्यालय का मामला

नवभारत, चुहिरी । नवभारत संवाददाता। जैतपुर क्षेत्र के बिरौड़ी स्थित एकलव्य विद्यालय में बुधवार को उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई, जब विद्यालय के करीब 200 विद्यार्थी प्राचार्य एवं विद्यालय की अव्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय शहडोल में कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल निकल पड़े। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के एक साथ विद्यालय से निकलकर शहडोल की ओर पैदल जाने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। बताया गया कि विद्यार्थी विद्यालय की व्यवस्थाओं तथा प्राचार्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से पैदल शहडोल जाने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों का यह पैदल मार्च करीब 15 किलोमीटर तक पहुंच गया।



शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती

विद्यार्थियों का कहना है कि विद्यालय से जुड़ी समस्याओं और प्राचार्य के संबंध में उनके द्वारा उठाई जा रही शिकायतों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी के चलते विद्यार्थियों ने सीधे कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताने का निर्णय लिया। करीब 200 विद्यार्थियों के इस तरह सामूहिक रूप से विद्यालय से बाहर निकलने की घटना ने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूचना मिलते ही प्रशासन हुआ सक्रिय

विद्यार्थियों के पैदल शहडोल की ओर जाने की जानकारी प्रशासन को मिलते ही अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस विद्यालय लाने के लिए प्रशासन की ओर से दो बसें भेजी गईं। इसके बाद विद्यार्थियों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्राचार्य से संबंधित शिकायतों को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल निकलने के मामले में अब जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विद्यार्थियों द्वारा बताई जा रही समस्याओं की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग उठ रही है। प्रशासन यदि विद्यार्थियों की शिकायतों की गंभीरता से जांच करता है तो विद्यालय की व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल विद्यार्थियों की शिकायतों और पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की जांच एवं आगामी कार्रवाई का इंतजार है।

एक नजर में



भाजपा की समीक्षा बैठक आज

नवभारत ,शहडोल। सेवा संकल्प अभियान के तहत संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्ययोजना को लेकर भाजपा की संगठनात्मक मासिक बैठक 8 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में संभाग प्रभारी गौरव सिरोठिया की उपस्थिति तथा भाजपा जिलाध्यक्ष अमिता चपरा की अध्यक्षता में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विनय केवट ने बताया कि बैठक गुरुवार को दोपहर 12 बजे कमला नगर स्थित संभागीय मुख्यालय 'अटल निलय' जिला भाजपा कार्यालय में होगी। इसमें सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अब तक आयोजित कार्यक्रमों की प्रगति, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संगठनात्मक तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में सांसद, विधायक, जिला संगठन प्रभारी, जिला पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष सहित विभिन्न मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री शामिल होंगे।

60 महिलाओं को मिली सिलाई किट

नवभारत, धनपुरी । एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सोहागपुर क्षेत्र बी.के. जेना ने क्षेत्र एवं आसपास के गांवों की 60 जरूरतमंद एवं इच्छुक महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई किट एवं बैग वितरित किए। यह पहल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनकी आय के साधन विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एसईसीएल मुख्यालय द्वारा संचालित इस पहल के तहत चयनित महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की जिम्मेदारी अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) को सौंपी गई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को आधुनिक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीनों के संचालन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं साधारण कपड़े से अलग-अलग प्रकार के गारमेंट तैयार करने की कला सीख रही हैं, जिससे प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद वे अपने स्तर पर सिलाई कार्य शुरू कर सकेंगी।

मेरे सपनों का भारत प्रतियोगिता में 275 छात्रों को दिए गए पुरस्कार

आईटीआई में सेवा संकल्प अभियान में मेधावी छात्र-छ त्राओं का सम्मान

नवभारत,गोहपारू । विधानसभा क्षेत्र 84 जयसिंहनगर अंतर्गत 'सेवा संकल्प अभियान-मेरे सपनों का भारत' के तहत बुधवार को गोहपारू स्थित आईटीआई परिसर में मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकासखंड गोहपारू के विभिन्न विद्यालयों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 275 छात्र-छात्राओं ने उपस्थित होकर सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त किए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक मनीषा सिंह रहीं। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रियम त्रिपाठी, चुहिरी मंडल अध्यक्ष राजीव तिवारी, गोहपारू मंडल अध्यक्ष राजीव शर्मा, उपाध्यक्ष अलख निरंजन सिंह, योगेश मिश्रा, नरेंद्र तिवारी एवं अतुल मिश्रा सहित भाजपा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्राचार्य, शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ललित कुमार पाण्डेय, लेखापाल उदय भान पाण्डेय, सहायक लेखापाल आर.के. सिंह, राजा भैया तिवारी, ओ.पी. द्विवेदी, बीआरसी लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी एवं बीएसी विजय प्रताप सिंह उपस्थित रहे।



शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित

वहीं संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य राहुल सिंह, गुर्रा के प्राचार्य अनिल कुमार द्विवेदी, अंकुरी के अमित सिंह बघेल, चुहिरी के अरुण कुमार मिश्रा, खन्नौधी के विष्णु मिश्रा, हाई स्कूल बुढ़नवाह के प्राचार्य अवधेश द्विवेदी, करीं के बनवीर सिंह, पैलवाह से मिथिलेश सोनी तथा गोड़ारू के प्राचार्य प्रदीप सिंह बघेल सहित विकासखंड के सभी हाई स्कूलों के प्राचार्य एवं शिक्षक मौजूद रहे।

विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित

समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और सफलता अन्य छात्र-छात्राओं के लिए भी प्रेरणा का कार्य करती है। ऐसे सम्मान समारोह से बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह और आगे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। 275 मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करना रहा।

बंद डिस्पेंसरी के दो कर्मचारियों को दिया वेतन

अमलाई खुली खदान के दो कर्मचारियों को कार्यमुक्त होने के बावजूद वेतन भुगतान

नवभारत , धनपुरी । साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र में जारी एक कार्यालय आदेश अब प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। 17 अगस्त को जारी आदेश क्रमांक 2722 में अमलाई ओसीएम डिस्पेंसरी से जुड़े दो कर्मचारियों को कार्यमुक्त करते हुए उन्हें अन्य स्थानों पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों कर्मचारी अमलाई ओसीएम डिस्पेंसरी से रिलीव किए गए हैं।

आदेश के अनुसार श्रीमती जॉली मैथ्यू, चीफ मैट्रन को बुढ़ार सेंट्रल हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल सर्विसेज के समक्ष रिपोर्ट करने तथा श्रीमती संगीता दुबे, चीफ फार्मासिस्ट को अमलाई-धनपुरी ओसीएम सब एरिया के सब एरिया मैनेजर के समक्ष आगे की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में यह भी दर्ज है कि संबंधित कर्मचारियों को अमलाई ओसीएम से विधिवत कार्यमुक्त किया गया है।

आदेश कागज पर हकीकत कुछ और

मामला यहीं से गंभीर हो जाता है। क्षेत्र में चर्चा है कि संबंधित



डिस्पेंसरी बंद हो चुकी हैं, इसके बावजूद यदि कर्मचारी पुराने स्थान से जुड़े वेतन और अन्य सेवा लाभ प्राप्त कर रहे हैं द्य और वहाँ बिना कार्य के लाखों का वेतन ले रहें जिससे गंभीर सवाल खड़ा होता है ऐसे मे इसका प्रशासनिक आधार क्या है। यदि दोनों कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए थे, तो क्या उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण किया। यदि किया तो उसकी उपस्थिति किस कार्यालय में दर्ज हो रही है।

श्रम संघ से संरक्षण

क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि दोनों कर्मचारियों को सोहागपुर क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ श्रम संघ पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यदि यह चर्चा निराधार है तो प्रबंधन को तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि इसमें कोई तथ्य है तो यह भी जांच का विषय है कि किसी कर्मचारी को जारी प्रशासनिक आदेश के बावजूद राहत कैसे मिल रही है।

मुख्य महाप्रबंधक और कार्मिक प्रबंधक से अपेक्षा

अब निगाहें सोहागपुर क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक और उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक पर हैं। सवाल यह है कि 17 अगस्त का आदेश जारी होने के बाद इसका वास्तविक पालन क्यों सुनिश्चित नहीं हुआ। क्या दोनों कर्मचारियों ने आदेशानुसार नई जगह पर कार्यभार ग्रहण किया? उनकी उपस्थिति कहां दर्ज हो रही है। यदि वेतन भुगतान जारी है तो किस कार्यालय की उपस्थिति और किस कार्य आवंटन के आधार पर क्या संबंधित अधिकारियों ने पिछले डेढ़ महीने में इस आदेश की अनुपालना की जांच की। प्रबंधन यदि यह दावा करता है कि आदेश का पूरी तरह पालन हो चुका है, तो दोनों कर्मचारियों की वर्तमान पदस्थापना, कार्यभार ग्रहण की तारीख और उपस्थिति का रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहिए।

मानवता की अनुपम सेवा है देहदान : न्यायाधीश खान

उल्लास कार्यक्रम में देहदान का संकल्प लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित

नवभारत , देपालपुर । गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के तत्वावधान में 'उल्लास' कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन, उनके सत्य, अहिंसा एवं स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को स्मरण करते हुए विभिन्न जागरूकता एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।

जिला न्यायाधीश खान ने की सराहना

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण देहदान का संकल्प लेने वाले परिवारों का सम्मान रहा। तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने देहदान के संकल्प को मानवता के प्रति अनुपम सेवा बताते हुए देहदानी परिवारों को शाल, श्रीफल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।इस अवसर पर जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि देहदान केवल मृत्यु के बाद शरीर का दान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, चिकित्सा और मानव सेवा का अमूल्य उपहार है।श्री खान ने हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह द्वारा सपत्नीक देहदान की घोषणा को प्रेरणा बताते हुए देहदान के प्रतिसमाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया।



भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

लालपुर बुढ़ार, शाखा (07223),
Lalpur Burhar Branch (07223)
वार्ड क्र. 05, शहडोल रोड, बुढ़ार, जिला-शहडोल, (म.प्र.)-484110
Ward No. 05, Shahdol Road, Burhar Distt. - Shahdol (M.P.) -484110

Final Notice to the Borrower
(Registered with AD)

Annexure: PL-58

सेवा मे,
श्री सचदेव कुमार जगवानी पुत्र श्री जीवत राम जगवानी,
काली मंदिर के पास, बुढ़ार, जिला - शहडोल, मध्य प्रदेश 484110

प्रिय महोदय/महोदया,
विषय 1,18,000/- रुपये के गोल्ड लोन खाता संख्या-44345415938 में लगातार अनियमितता के संबंध में अंतिम सूचना।
हमारे पत्र संख्या "गोल्ड लोन 01, दिनांक 03.09.2026" एवं पत्र संख्या "गोल्ड लोन 04, दिनांक 24.09.2026" के द्वारा आपसे अपने गोल्ड लोन खाते को नियमित करने का अनुरोध किया गया था। आपके खाते में ब्याज एवं मूलधन की बकाया राशि अब 19,054/- रुपये एवं अर्जित ब्याज तथा अन्य बैंक भार तक पहुँच गयी है।
अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के भीतर ऋण खाता नियमित / बंद कर दें।
हम एतद् द्वारा आपको अंतिम सूचना देते हैं कि यदि ऋण खाता एक माह की अवधि के भीतर बंद नहीं किया जाता है, तो ऋण की सुरक्षा के रूप में रखे गए आभूषणों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा, तथा आपसे किसी भी कमी/बकाया राशि की वसूली के लिए आप अपने वचन पत्र के आधार पर उत्तरदायी होंगे।
सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी की प्रस्तावित तिथि और स्थान निम्नानुसार है :
दिनांक :- 24.10.2026, स्थान :- भारतीय स्टेट बैंक लालपुर बुढ़ार शाखा, शाखा कोड : 07223
आज्ञा से,
शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
लालपुर बुढ़ार, ब्रांच (07223)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

लालपुर बुढ़ार, शाखा (07223),
Lalpur Burhar Branch (07223)
वार्ड क्र. 05, शहडोल रोड, बुढ़ार, जिला-शहडोल, (म.प्र.)-484110
Ward No. 05, Shahdol Road, Burhar Distt. - Shahdol (M.P.) -484110

Final Notice to the Borrower
(Registered with AD)

Annexure: PL-58

सेवा मे,
श्री सचदेव कुमार जगवानी पुत्र श्री जीवत राम जगवानी,
काली मंदिर के पास, बुढ़ार, जिला - शहडोल, मध्य प्रदेश 484110

प्रिय महोदय/महोदया,
विषय- 1,10,800/- रुपये के गोल्ड लोन खाता संख्या 44354205351 में लगातार अनियमितता के संबंध में अंतिम सूचना।
हमारे पत्र संख्या "गोल्ड लोन 02, दिनांक 09.09.2026" एवं पत्र संख्या "गोल्ड लोन 05, दिनांक 24.09.2026" के द्वारा आपसे अपने गोल्ड लोन खाते को नियमित करने का अनुरोध किया गया था। आपके खाते में ब्याज एवं मूलधन की बकाया राशि अब 17,889/- रुपये एवं अर्जित ब्याज तथा अन्य बैंक भार तक पहुँच गयी है।
अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के भीतर ऋण खाता नियमित / बंद कर दें।
हम एतद् द्वारा आपको अंतिम सूचना देते हैं कि यदि ऋण खाता एक माह की अवधि के भीतर बंद नहीं किया जाता है, तो ऋण की सुरक्षा के रूप में रखे गए आभूषणों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, तथा आपसे किसी भी कमी/बकाया राशि की वसूली के लिए आप अपने वचन पत्र के आधार पर उत्तरदायी होंगे।
सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी की प्रस्तावित तिथि एवं स्थान निम्नानुसार है :
दिनांक :- 24.10.2026, स्थान :- भारतीय स्टेट बैंक लालपुर बुढ़ार, शाखा, शाखा कोड : 07223
आज्ञा से,
शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक
लालपुर बुढ़ार, ब्रांच (07223)

हड़ताल दिव्या सिंह को हटाने और पूरे वेतन के लिए अड़े पटवारी

तहसीलदार ने नहीं लिया ज्ञापन, पटवारी हड़ताल पर

नवभारत,शहडोल । जिले में पटवारियों की हड़ताल अब केवल विभागीय विवाद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका सीधा असर ग्रामीणों और किसानों पर पड़ने लगा है। राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्यों के लिए तहसील और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

किसान सबसे ज्यादा परेशान

सबसे ज्यादा चिंता उन किसानों की बढ़ गई है, जिन्हें धान विक्रय के लिए पंजीयन संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी है। शासन स्तर पर धान विक्रय पंजीयन की अंतिम तिथि ''10 अक्टूबर'' निर्धारित है और अब इसमें महज तीन दिन शेष हैं।पटवारियों के हड़ताल पर रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व से जुड़े विभिन्न कार्य प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। किसानों को भूमि संबंधी जानकारी, रिकॉर्ड, सत्यापन और अन्य आवश्यक राजस्व प्रक्रियाओं के लिए पटवारी स्तर पर काम पड़ता है। ऐसे में हड़ताल लंबी खिंचने पर समय सीमा से जुड़े कामों को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।

धान पंजीयन की अंतिम तिथि करीब

धान खरीदी के लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया में समय तेजी से निकल रहा है। 10 अक्टूबर अंतिम तिथि होने के कारण किसानों के पास अब केवल तीन दिन का समय बचा है। ऐसे में जिन किसानों के पंजीयन या उससे जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन का काम लंबित है, उनके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।ग्रामीणों का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि पंजीयन नहीं हो पाया तो उन्हें धान विक्रय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि किसान चाहते हैं कि प्रशासन तत्काल ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करे, जिससे हड़ताल के बावजूद जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सकें।हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी काम प्रभावित होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ रही है। कई लोग पहले से निर्धारित कार्यों को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन संबंधित स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने की स्थिति में उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय विवाद का खामियाजा आम लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। प्रशासन को कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के साथ-साथ आम जनता से जुड़े जरूरी कामों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए।

वेतन कटौती और लंबित भुगतान को लेकर पटवारियों में नाराजगी

पटवारियों का कहना है कि उनकी कई सेवा संबंधी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। अलग-अलग तहसीलों में वेतन कटौती, सेवा पुस्तिका तैयार नहीं होने, एरिया और टीए-डीए सहित अन्य देयकों के भुगतान का मामला उठाया गया है। उनका आरोप है कि कई बार अधिकारियों के सामने समस्याएं रखने के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं हुआ।पटवारियों की ओर से निलंबित कर्मचारियों की वापसी तथा नवनियुक्त पटवारियों को जारी सेवा समाप्ति के नोटिस पर पुनर्विचार की मांग भी की जा रही है।

इनका कहना है

गोहपारू तहसील में पटवारियों साथियों का 1 माह का वेतन काट दिया गया, जिसके सम्बंध में तहसीलदार को ज्ञापन प्रेषित करने हम सभी पटवारीगण पहुँचे किन्तु तहसीलदार द्वारा कहा गया कि ज्ञापन भृत्य को दे दो और जाओ, ज्ञापन अस्वीकार करना हम सभी की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है। आंदोलन के माध्यम से पटवारियों ने तहसीलदार दिव्या सिंह को हटाने की मांग भी उठाई है।

सत्यप्रकाश मिश्रा, जिलाध्यक्ष, म.प्र.पटवारी संघ,जिला शहडोल

पहले किसान, विवाद का समाधान

पटवारियों की मांगें अपनी जगह हैं और प्रशासन के सामने विभागीय गतिरोध समाप्त करने की चुनौती है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन किसानों और ग्रामीणों का है, जिनके काम समय सीमा से बंधे हैं।धान पंजीयन की अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण प्रशासन के सामने तत्काल चुनौती है कि किसानों के पंजीयन और अन्य जरूरी राजस्व कार्य प्रभावित न हों। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ पटवारियों से बातचीत कर गतिरोध समाप्त करना जरूरी हो गया है।